टूटी कोहनी में राड़ डालने के 15,000 देने पड़े

'बीके हॉस्पिटल' में भ्रष्टाचार की थाह पाना संभव नहीं

सत्यवीर सिंह

फरीदाबाद। सुभाष, अपने 70 वर्षीय पिताजी, ननहके जी के साथ, फ़रीदाबाद के सेक्टर 21 सी में, सड़क किनारे, कपड़े स्त्री कर और कई घरों में जाकर कपडे धोकर अपना जीवन-यापन करते हैं. ननहके जी, एक दिन जब पास के ठेले से सब्जी ख़रीद रहे थे, तब एक रईसज़ादे ने अपनी 'मॉड' साईकल से टक्कर मार दी और चलता बना. वे ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी कलाई की हड्डी टूट गई. ये बात अप्रैल 2022 की है. अपना टूटा हाथ लेकर, वे कई दिनों तक, शहर में स्वास्थ्य की निजी दुकानों पर, हड्डी जोड़ने का रेट पूछते घूमे, लेकिन कहीं भी इस ऑपरेशन का भाव 60,000/ रु से नीचे नहीं मिला. वे इतनी रक़म जुटाने में असमर्थ थे. तब ही उनके एक साथी ने, उन्हें शहर के सरकारी ज़िला चिकित्सालय, बादशाह खान (बीके) अस्पताल जाने की सलाह दी. सलाह देने वाले मित्र बीके अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उनकी समझ थी कि रिश्वत देकर भी उनका खर्च,स्वास्थ्य के नाम पर चल रही इन चमचमाती निजी दुकानों से तो कम ही आएगा.

सुभाष और उनके पिताजी 30 अप्रैल 2022 को बीके अस्पताल पहुंचे और शुरू हुआ लाइन में लगने, बार-बार दुत्कारे जाने, अस्पताल के सामने जाँच केन्द्रों पर, जाँच करा-करा कर लाने का अंतहीन सिलसिला. तब ही इस मौजूदा सड़ी हुई पूंजीवादी व्यवस्था की सड़ी पैदाइश, एक 'दलाल' ने उन्हें सुझाया कि 'खर्च' करना पड़ेगा, वरना टूटी हुई हड्डी लेकर ही घर लौटना पड़ेगा!! हड्डी टूटने और बार-बार टेस्ट कराने के चक्कर में भटकने, और अपनी दिहाड़ी खोते जाने के दर्द से, कराह बाप-बेटों ने 'खर्च' का जुगाड़ कर लिया. कई दिन भटकने और टेस्ट के खर्च के अलावा, 15,000/ रु मान सिंह यादव पुत्र हीरा लाल यादव, मोबाइल नंबर 9971760622 को गूगल पे (Transaction ID CICAg®DTzPKTHg) से ट्रान्सफर करने के बाद, 4 मई को ननहके जी के हाथ की कलाई का ऑपरेशन हुआ और उसमें रॉड डल गई. 'जाओ अब 6 महीने बाद आना, फिर ऑपरेशन होगा और ये रॉड निकाली जाएगी', सुनकर बाप-बेटा, दोनों अपने काम पर लग गए. बाक़ी वे अब जान ही चुके थे कि क्या करना होता है!!

तय हुआ कि सुभाष, अपने पिताजी के साथ 24 जनवरी को सुबह 8 बजे, बी के अस्पताल जाएँगे, और जैसे ही निर्धारित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है; रिश्वतखोरी की ख्वाहिश की दुर्गन्ध जैसे ही महसूस होती है, बाक़ी टीम मेंबर भी पहुँच जाएंगे. 12 बजे सुभाष की कॉल आ गई, आ जाईये. कॉमरेड सुभाष ने सारी आप बीती सुनाई, तो तय हुआ कि इस अस्पताल का रोग गंभीर है. इसलिए, सबसे पहले, सबसे बड़ी डॉक्टर और प्रशासक पीएमओ को सारी हकीक़त बताई जाए. मई का तजुर्बा उन्हें बताया गया, टेस्ट कराने, बार-बार बुलाकर सताने, पैसे ऐंठने की दास्ताँ और उसी तर्ज़ पर 24 जनवरी के अनुभव को जानने के बाद, पीएमओ मैडम ने हैरानी जताई, 'हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता' बोला और अपने वरिष्ठ डॉक्टरों को अपने चैम्बर में तलब किया. तब ही उन्हें कोई अति महत्वपूर्ण कॉल आ गई और सभी लोग दूसरे कैबिन में शिफ्ट हो गए.

'हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर रिश्वत मांगे या मरीज़ को आतंकित करे', विषय पर हो रही चर्चा में एक डॉक्टर और शामिल हो गए. सुभाष और उनके पिताजी ने गौर से देखा और चीख पड़े, 'दस हज़ार की रिश्वत मांगने वाला डॉक्टर तो ये ही है, हम अच्छी तरह पहचानते हैं'!! दोनों ने एक साथ ऊँगली जिस शख्स के मुंह की ओर उठाई, उनका नाम डॉक्टर अभिषेक वार्ष्णेय है. क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा टीम के सदस्य कॉमरेड नरेश जो 'मज़दूर समाचार' चेनल भी चलाते हैं , कॉमरेड सत्यवीर और कॉमरेड ब्रिजेश ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. डॉक्टर वार्ष्णेय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं. 'मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है', डॉक्टर साहब के मुंह से ये ध्वनि निकली ज़रूर, लेकिन उस अंदाज़ में नहीं, जैसी किसी बेक़सूर पर ऐसा गंभीर आरोप लगने पर निकलती है. दूसरी हैरान करने वाली बात ये थी कि उस वक़्त मौजूद किसी भी दूसरे डॉक्टर ने, डॉक्टर वार्ष्णेय पर रिश्वत का आरोप लगने पर, हैरानी नहीं जताई. दूसरी ओर, सुभाष और उनके पिताजी ननहके की आवाज़ में सच्चाई की रोषपूर्ण तल्खी बढ़ती गई.

'आपने, ये क्यों कहा कि आपने मेरा ऑपरेशन किया है, 10,000/ फिर खर्च करने पड़ेंगे जबकि मैं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को अच्छी तरह पहचानता हूँ कि वो आप ही हैं!!' ननहके, भावावेश में ऊँचे हाथ उठाकर बोलते गए, 'मुझे अपने बच्चों, अपने भगवान की क़सम है, अगर मेरी बात झूट हो, तो मुझे फांसी दे दी जाए, इसी डॉक्टर ने मुझसे पैसे मांगे थे'. डॉक्टर वार्ष्णेय का चेहरा असलियत बयान कर रहा था. सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनके किसी भी सहयोगी ने, डॉक्टर वार्ष्णेय पर इतने संगीन आरोप सरे आम, सारे स्टाफ के सामने लगने पर भी ना हैरानी जताई, ना उनके बचाव में एक शब्द भी बोला. इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी छवि किस तरह की है. यहाँ सुभाष और उनके पिताजी ननहके के इस बयान को भी पढ़ा जाए कि उन्होंने जितनी बुलंद आवाज़ और सच्चाई के साथ डॉक्टर अभिषेक वार्ष्णेय पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, उतनी ही तीव्रता के साथ ये भी बोला कि डॉक्टर सतीश वर्मा ने उन्हें बोला था कि किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन बिना कोई पैसा खर्च किए होगा.

मामला संगीन अपराध का बन चुका था, इसलिए सभी लोग पीएमओ मेडम के चैम्बर में पहुँच गए. पीएमओ ने पूरे मामले की पूरी जाँच कराने और दोषियों को दण्डित करने का आश्वासन दिया. उनके कथन का विश्वास किया जाना चाहिए लेकिन औपचारिक शिकायत दर्ज कर, दो लाख वेतन पाने वाले डॉक्टर द्वारा, दिनभर पसीना बहाकर मुश्किल से दो जून रोटी खाने वाले मज़दूरों को लूटने की बेगैरती और अक्षम्य अपराध की इस घटना से नज़र हटने नहीं दी जानी चाहिए. प्रस्तावित जाँच एजेंसी को, इस

रिश्वतखोर : डॉक्टर अभिषेक

रिश्वत के शिकार : सुभाष 70 वर्षीय पिता ननहके के साथ

रिश्वतखोरी के अतिरिक्त, बी के

अस्पताल में व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार के दूसरे तरीकों को भी बताया जाना ज़रूरी है. ननहके जी के हाथ में हड्डी जोड़ने और उसमें रॉड डालने का ऑपरेशन, लोकल अनेस्थिसिया से हो गया. अब उस रॉड को निकालने का ऑपरेशन क्या उससे ज्यादा गंभीर है, जो पूरे शरीर को अनेस्थिसिया देकर होना है? इस प्रक्रिया में उन्हें दिल की ईको जाँच करानी होगी जिसका ख़र्च बाज़ार में 2,500 रु है. इस जाँच का रहस्य, सरकारी-निजी साझेदारी (PPP) के नाम पर सरकारी इदारों को निजी पूंजी के हवाले करने वाली साझे की दुकान, 'हृदय उपचार विभाग' में काम कर रहे एक ज़िम्मेदार कर्मचारी ने स्पष्ट कर दिया. 'हमारी इको मशीन 6 महीने से बंद पड़ी है, हॉस्पिटल का हर डॉक्टर जानता है लेकिन मरीज़ के सामने भोलापन और झूटी हमदर्दी दिखाते हुए, उसे टेस्ट के लिए यहाँ भेजा जाता है. बाहर टेस्ट की दुकानें लाइन से खुली हुई हैं जिनमें 50 प्रतिशत कमीशन का रेट है. एक ईको टेस्ट का मतलब, मरीज़ की जेब से 2,500/ रु निकलकर, 1,250/ रु डॉक्टर की जेब में पहुँच जाएँगे.' डॉ राजेश धीमान ने ग़रीब मज़दूर के प्रति संवेदनाशीलता दर्शाते हुए, अपने व्यक्तिगत प्रयास से, ननहके जी का ईको टेस्ट एक निजी अस्पताल में निशुल्क कराया, ये तथ्य रिपोर्ट करते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है.

हॉस्पिटल में टेस्ट करने की जितनी मशीनें बंद रहेंगी, डॉक्टरों की कमाई उसी अनुपात में अधिक होगी. इसीलिए ज्यादातर टेस्ट मशीनें ख़राब ही रहती हैं. सरकारी अस्पतालों द्वारा जन-स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क़ तो सरकार ने ही किया हुआ है. स्वास्थ्य बजट, ज़रूरत के मुकाबले नगण्य है. अस्पताल ही पर्याप्त नहीं. डॉक्टरों और सहायक स्टाफ की भारी कमी है. दवाईयों की शेल्फ़ ख़ाली रहती हैं. ऑपरेशन थिएटर ज़र्ज़र हैं, सफ़ाई के ये हाल हैं कि अन्दर घुसते ही उबकाई आती है. इस मुद्दे पर तो देश स्तर पर तीखे जन-आन्दोलन, यदि अभी भी नहीं छेड़े गए तो आने वाले एक-दो सालों में सब सरकारी अस्पतालों पर भी अडानी-अम्बानी के नाम लिखे होंगे. साथ ही, सरकारी अस्पतालों में, डॉक्टरों की मरीजों के प्रति संवेदनहीनता और यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, ग़रीबों का ईलाज असंभव बना दे रहे हैं. अनावश्यक टेस्ट लिखते जाना, अस्पताल की मशीनें ख़राब रखना, सिसकते मरीज़ों की जेबें काटना बीके अस्पताल का दस्तूर है.

स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य की क्या करेंगे देखभाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) संघ प्रशिक्षित मुख्यमंत्री खट्टर को पूरा विश्वास है कि जनता को बेवकूफ बनाये रखने के लिये मीडिया के माध्यम से लोक-लुभावनी घोषणायें करते रहना ही काफी है। इसके अलावा धरातल पर कोई भी ठोस काम करने की आवश्यकता नहीं है।

अपनी इसी समझदारी के तहत खट्टर सरकार लगातार यह घोषणा किये जा रही है कि सरकारी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच का विशेष कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े व रिकॉर्ड तैयार किये जायेंगे। विज्ञान अध्यापकों को इस बाबत कुछ गुर भी सिखाये जायेंगे। इनके आधार पर अध्यापक बीके अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से सलाह-मश्वरा करके बच्चों का इलाज करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को अस्पताल भी ले जायेंगे।

सर्वविदित है कि स्कूलो में न तो पर्याप्त मास्टर है और न ही अस्पतालों में डॉक्टर व अन्य स्टाफ़। स्कूलों में सबसे ज्यादा कमी विज्ञान और गणित अध्यापकों की है। और जो हैं भी उन्हें पढ़ाई के काम के अलावा अन्य सभी तरह के कामों, मसलन चुनाव, जनगणना, सर्वे राशन कार्ड सम्बन्धी, में उलझाये रखा जाता है। सरकार ने उन पर पहले से ही इतने वाहियात के काम लाद रखे हैं कि वे इस नये बोझ को उठा पाने में सक्षम नजर नहीं आते। इसके अलावा सरकार मर्जर के नाम पर धड़ाधड़ स्कूलों को बंद किये जा रही है। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो किन बच्चों के स्वास्थ्य की जांच खट्टर महाशय करायेगे?

दूसरी ओर एक बीके अस्पताल ही नहीं राज्य भर के तमाम अस्पताल खुद ही बीमार पड़े हैं तो वे क्या इन बच्चों का इलाज करेंगे? सरकारी घोषणा के अनुसार इन्ही अस्पतालों से डॉक्टर स्कूलों में जाकर बच्चों की देख-भाल भी करेंगे। सरकारी अस्पतालों से वास्ता रखने वाले भुक्तभोगी बखूबी जानते हैं कि इन अस्पतालों में कैसा इलाज होता है? ओपीडी में मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि वहां पर खड़े हो पाना भी आसान नहीं होता। ऐसे में स्कूल वाले अपने बच्चों को वहां ले जाकर क्या करेंगे? हां, यदि किसी को इन अस्पतालों में जाना ही होगा तो वे सीधे ही अपने अभिभावकों के साथ चले जायेंगे। इसके लिये उन्हें खट्टर की इस स्वास्थ्य योजना के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वैसे यह सब तो खट्टर भी जानते हैं, उन्हें सब पता है कि स्कूलों में न तो किसी की जांच होनी है न किसी मास्टर ने कोई रिकॉर्ड तैयार करना है और न ही किसी डॉक्टर ने स्कूलों में जाकर बच्चों की देख-भाल करनी है। इस तमाम सच्चाई को जानते हुए भी खट्टर सरकार द्वारा इस तरह की घोषणायें केवल इसलिये की जाती हैं कि जनता यह समझती रहे कि सरकार उनके प्रति कितनी चिंतित है और उनके भले के लिये क्या-क्या नहीं कर रही।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।